

हरियाणा राज्य बनाम रामदत्त उप अधीक्षक ऑफ हरियाणा
 पुलिस (कृष्ण मुरारी, मुख्य न्यायाधीश)
 कृष्ण मुरारी, सी. जे. और अरुण पल्ली, जे.
 हरियाणा राज्य-अपीलार्थी
 बनाम

रामदत्त उप अधीक्षक ऑफ पुलिस
 उत्तरदाता

2017 का एल. पी. ए. No.1353

05 सितंबर, 2019

लेटर्स पेटेंट-खंड X-मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक के अधिग्रहण पर एक अग्रिम वृद्धि देने की नीति-याचिकाकर्ता ने पुलिस पदक अर्जित किया और उसे सेवा में एक साल का विस्तार दिया गया-विस्तारित सेवा के दौरान अग्रिम वार्षिक वृद्धि का दावा राज्य द्वारा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि नीति वापस ले ली गई थी-नई नीति के बजाय सेवा में एक साल के विस्तार का प्रोत्साहन दिया गया-विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को 2004 की नीति के तहत पदक के लिए एक अग्रिम वृद्धि का हकदार ठहराया, और सेवा के विस्तार के दौरान अतिरिक्त वृद्धि का नहीं-आयोजित किया गया, क्योंकि 2004 की नीति की समीक्षा की गई और 2010 की नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जहां एकमात्र स्वीकार्य लाभ के तहत सेवा का एक साल का विस्तार था जिसका लाभ याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया था-विस्तारित सेवा के दौरान गलती से दी गई अग्रिम वृद्धि का लाभ, सही था।

यह माना गया कि जब अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान अतिरिक्त वृद्धि का लाभ दिया गया था, तो 2004 की नीति की समीक्षा की गई थी और 2010 की एक नई नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसके तहत एकमात्र स्वीकार्य लाभ सेवा में एक वर्ष का विस्तार था। तदनुसार, उनकी सेवा अवधि एक वर्ष डब्ल्यू. ई. एफ. 01.09.2010 की अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी, जब आम तौर पर वे 31.08.2011 पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाते। उक्त लाभ अपीलार्थी-याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया था जो नई नीति के तहत स्वीकार्य था। सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान उन्हें गलती से अग्रिम वृद्धि का लाभ दे दिया गया था, हालांकि सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान सामान्य रूप से ऐसा कोई लाभ इस आधार पर स्वीकार्य नहीं था कि वह पुलिस पदक के विजेता थे।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

राज्य ने बाद में गलती का एहसास करते हुए समीक्षा की और कई अन्य समान रूप से स्थित अधिकारियों के साथ मामला और उसी को वापस ले लिया।

(पैरा 11)

यह भी अभिनिर्धारित किया कि विद्वत एकल न्यायाधीश ने हालांकि अभिनिर्धारित किया है कि सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान अपीलार्थी-याचिकाकर्ता किसी भी अग्रिम वेतन वृद्धि के अनुदान का हकदार नहीं होगा, लेकिन 2004 की नीति के तहत पुलिस पदक से सम्मानित होने के कारण एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करने का निर्देश दिया है, जो कि अस्तित्व में ही नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य को ध्यान में रखने में भी विफल रहे हैं कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता पहले ही नई नीति के तहत एक वर्ष की सेवा अवधि के विस्तार का लाभ उठा चुका है और इस प्रकार वह पुरानी नीति के तहत किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा जो वापस ले ली गई है/हटा दी गई है।

(पैरा 12)

कर्तार सिंह माली-1, अधिवक्ता

2017 के एल. पी. ए. सं. 1830 में अपीलार्थी के लिए;

2017 के एल. पी. ए. सं. 1353 में प्रत्यर्थी के लिए,

दीपक बालियान, ए. ए. जी., हरियाणा

2017 के एल. पी. ए. सं. 1353 में अपीलार्थी के लिए

2017 के एल. पी. ए. सं. 1830 में प्रत्यर्थी के लिए।

कृष्णा मुरारी, चीफ जस्टिस

(1) इन अंतर-न्यायालय अपीलों में से एक हरियाणा राज्य (रिट याचिका में प्रतिवादी) द्वारा दायर की गई है और दूसरी अपीलार्थी-याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है क्योंकि ये विद्वान एकल न्यायाधीश के सामान्य निर्णय के खिलाफ निर्देशित हैं, इसलिए इन्हें एक साथ जोड़ा गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा तय किया जा रहा है।

(2) विद्वान एकल न्यायाधीश ने दोनों अपीलों में आक्षेपित आदेश के माध्यम से सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के अधिग्रहण के कारण एक अग्रिम वृद्धि के लिए अपीलार्थी-याचिकाकर्ता

के दावे को स्वीकार करते हुए सेवा अवधि के विस्तार के दौरान अतिरिक्त वृद्धि देने के उनके दावे को खारिज कर दिया। उक्त दावे को अस्वीकार करने वाले आदेश के हिस्से को अपीलार्थी-याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है, जबकि हरियाणा राज्य आदेश के हिस्से के खिलाफ अपील में आया है जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी-याचिकाकर्ता मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक के अधिग्रहण के लिए एक अग्रिम वृद्धि का लाभ देने का हकदार होगा।

(3) विवाद के निर्णय के उद्देश्य से संक्षेप में प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

- हरियाणा राज्य बनाम रामदत्त उप अधीक्षक ऑफ पुलिस

(कृष्ण मुरारी, मुख्य न्यायाधीश)

याचिकाकर्ता ने उप निरीक्षक के रूप में सेवा करते हुए 26.01.2001 पर सराहनीय सेवा का पुलिस पदक अर्जित किया। इसके बाद 2004 में उन्हें इंस्पेक्टर के पद पर और उसके बाद 2010 में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर उन्हें एक वर्ष के लिए डब्ल्यू. ई. एफ. 01.09.2010 से 31.08.2011 तक सेवा का विस्तार दिया गया। विस्तार अवधि समाप्त होने के बाद और अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने 31.08.2011 पर सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद, उन्होंने W. E. F. 15.02.2010 सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान अग्रिम वार्षिक वृद्धि के लाभ का दावा करते हुए 17.01.2014 दिनांकित एक अभ्यावेदन दिनांकित 10.6.2014 किया। राज्य द्वारा इस दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सरकार द्वारा पुनर्विचार करने पर मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक के पुरस्कार के कारण अग्रिम वार्षिक वृद्धि प्रदान करने के लिए दिनांकित 21-10-2004 के निर्णय को वापस लेने का निर्णय लिया गया था और इसके बजाय सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा में विस्तार का प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार उन्हें सेवा के विस्तार का लाभ दिया गया था और वे किसी भी अग्रिम वार्षिक वृद्धि के हकदार नहीं थे।

(4) चूंकि अपीलार्थी-याचिकाकर्ता को सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान गलत तरीके से वेतन वृद्धि दी गई थी, इसलिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के कार्यालय से प्राप्त एक संदर्भ पर इस मामले पर पुनर्विचार किया और सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान दी गई एक वेतन वृद्धि का लाभ वापस लेने के बाद अपीलार्थी-याचिकाकर्ता के वेतन को फिर से निर्धारित करने के लिए एक आदेश दिनांकित 11-9-2015 पारित किया। इस तरह की समीक्षा अन्य समान रूप से स्थित पुलिस अधिकारियों के संबंध में भी की गई और उन्हें दिए गए लाभ को भी वापस ले लिया गया। इस आदेश को अपीलार्थी-याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में भी चुनौती दी गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसे गलत तरीके से वापस ले लिया गया था।

(5) याचिका को हरियाणा राज्य द्वारा एक लिखित बयान दायर करके चुनौती दी गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अग्रिम वृद्धि का हकदार नहीं था कि उसे सेवा के विस्तार का लाभ दिया गया है। हालांकि,

2004 की कुछ नीतियों पर भरोसा करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक के अधिग्रहण के लिए एक अग्रिम वृद्धि का हकदार था और इस प्रकार उक्त लाभ उसे दिया जाना चाहिए।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

हालांकि, अतिरिक्त वृद्धि का दावा उनकी सेवा अवधि के विस्तार के दौरान इस आधार पर इनकार कर दिया गया था कि इसके लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था।

(6) हमने अपीलार्थी-याचिकाकर्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(7) अभिलेख के अवलोकन से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार ने दिनांक 12-06-2003 के ज्ञापन के माध्यम से ऐसे राजपत्रित पुलिस अधिकारियों/कर्मियों को सेवानिवृत्ति की आयु से परे सेवा में एक वर्ष/दो वर्ष का विस्तार देने का निर्णय लिया था, जो पुलिस कर्तव्यों और संतोषजनक सेवा रिकॉर्ड का निर्वहन करने के लिए शारीरिक योग्यता के अधीन पुलिस पदक प्राप्त करते हैं और यह निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदक का नाम	वित्तीय लाभ	सेवा लाभ
1	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	-	सेवा में दो साल का विस्तार
2	वीरता के लिए पुलिस पदक	-	सेवा में एक वर्ष का विस्तार।
3	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	-	सेवा में दो साल का विस्तार
4	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	-	सेवा में एक वर्ष का विस्तार

(8) 21.10.2004 दिनांकित एक अन्य ज्ञापन के माध्यम से, पुलिस उपाधीक्षक को निम्नलिखित प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया, जो पुलिस पदक के विजेता थे जो निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदक का नाम	प्रोत्साहन
1	राष्ट्रपति का पुलिस पदक विशिष्ट सेवा।	दो अग्रिम वृद्धि
2	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक।	एक अग्रिम वृद्धि।

(9) मामले पर पुनर्विचार करने पर, 10.06.2014 दिनांकित आदेश के माध्यम से, अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए 21.10.2004 दिनांकित निर्णय को वापस लेने का निर्णय लिया गया। ऐसे राजपत्रित गैर आई. पी. एस., डी. एस. पी./अतिरिक्त एस. पी. जो पुलिस पदक के प्राप्तकर्ता थे, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतम एक वर्ष के लिए सेवा में विस्तार का प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया।

हरियाणा राज्य बनाम रामदत्त उप अधीक्षक ऑफ पुलिस
(कृष्ण मुरारी, मुख्य न्यायाधीश)

(10) यह एक स्वीकृत स्थिति है कि वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ अपीलार्थी-याचिकाकर्ता को सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान इस आधार पर दिया गया था कि उन्हें 2001 में उप निरीक्षक के रूप में सेवा करते हुए पुलिस पदक दिया गया था।

(11) मान लीजिए, जब अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान अतिरिक्त वृद्धि का लाभ दिया गया था, तो 2004 की नीति की समीक्षा की गई थी और 2010 की एक नई नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसके तहत एकमात्र स्वीकार्य लाभ सेवा में एक वर्ष का विस्तार था। तदनुसार, उनकी सेवा अवधि एक वर्ष डब्ल्यू. ई. एफ. 01.09.2010 की अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी, जब आम तौर पर वे 31.08.2011 पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाते। उक्त लाभ अपीलार्थी-याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया था जो नई नीति के तहत स्वीकार्य था। सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान उन्हें गलती से अग्रिम वृद्धि का लाभ दे दिया गया था, हालांकि सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान सामान्य रूप से ऐसा कोई लाभ इस आधार पर स्वीकार्य नहीं था कि वह पुलिस पदक के विजेता थे। राज्य ने बाद में गलती का एहसास करते हुए इसी तरह के कई अन्य अधिकारियों के साथ मामले की समीक्षा की और इसे वापस ले लिया।

(12) विद्वान एकल न्यायाधीश ने हालांकि यह अभिनिर्धारित किया है कि सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता किसी भी अग्रिम वेतन वृद्धि के अनुदान का हकदार नहीं होगा, लेकिन 2004 की नीति के तहत पुलिस पदक से सम्मानित होने के कारण एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करने का निर्देश दिया है जो कि बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य को ध्यान में रखने में भी विफल रहे हैं कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता पहले ही नई नीति के तहत एक वर्ष की सेवा अवधि के विस्तार का लाभ उठा चुका है और इस प्रकार वह पुरानी नीति के तहत किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा जो वापस ले ली गई है/हटा दी गई है।

(13) उपरोक्त तथ्यों और चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित निर्णय में रिकॉर्ड के सामने एक त्रुटि स्पष्ट है और इस प्रकार इसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसके द्वारा आंशिक रूप से अलग रखा जाता है। अपीलार्थी-याचिकाकर्ता द्वारा

दायर 2017 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1830 तदनुसार खारिज हो जाती है, जबकि हरियाणा राज्य द्वारा दायर 2017 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1353 की दर्ज अनुमति है।

त्रिभुवन धैया

प्रवीण वर्मा

स्पष्टीकरण:— स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारीक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और क़ायान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।